प्रभात खबर

पटना, गुरुवार, 23 सितंबर, 2010

लोकप्रियता के दम पर लौट पायेंगे नीतीश!

कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता के दम पर पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता दिलाने में सफल रहे. इस समय नीतीश अपनी पार्टी से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं. हालांकि, जदयू के अधिकांश मतदाता, खासकर मुसलिम, ऐसे भी हैं जो भाजपा के साथ गंठबंधन को पसंद नहीं करते हैं. बावजूद इसके, नेता के रूप में नीतीश उनकी पहली पसंद बने हुए हैं. संभावना जतायी जा रही है कि उनकी यह लोकप्रियता जदयू-भाजपा गंठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में मददगार साबित होगी.

संजय कुमार

बिहार में जदयू सरकार को न सिर्फ विकास, बल्कि कुशल नेतृत्व के मामले में भी बढ़त हासिल है. इस समय नीतीश कुमार न केवल राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तुलना में भी उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है. कई अन्य लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, शीला दीक्षित आदि, ने अपने-अपने राज्यों में दोबारा सत्ता हासिल करने में सफलता पायी. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जदयू- भाजपा गंठबंधन को भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता का लाभ मिलेगा.

कुछ लोगों का मानना है कि हाल में अखबारों में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश की तसवीर छपने, इसके बाद उनके द्वारा भाजपा नेताओं के सम्मान में आयोजित भोज रद्द करने, कोसी राहत कोष में गुजरात सरकार द्वारा दिया पैसा वापस करने से नीतीश की लोकप्रियता घटी है. बावजूद इसके, वे बिहार में अब भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं. लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जैसे वरिष्ठ नेता इस समय नीतीश की लोकप्रियता का मुकाबला शायद ही कर पायेंगे.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, दिल्ली द्वारा विभिन्न चुनावों के दौरान कराये अपने सर्वे में पाया कि 'जनता दल' से अलग होकर 'समता पार्टी' का गठन करने और फिर 1995 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद से नीतीश की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. हालांकि, 1995 से 2000 के बीच यह बढ़ोतरी कुछ खास नहीं रही, लेकिन इस दौरान उनके विरोधी लालू प्रसाद की लोकप्रियता में गिरावट आयी. ऐसा लालू की जगह राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के कारण भी हुआ. यह वह समय था, जब रामविलास पासवान की लोकप्रियता बढ़ रही थी. फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय, तो वे मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभरे थे. उस चुनाव के दौरान कराये गये सर्वे में 30 फीसदी लोगों ने पासवान को मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य बताया था, जबकि 22 फीसदी ने नीतीश को पसंद किया था. फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा सामने आयी और किसी सरकार का गठन नहीं हो सका. मजबूरन, इसी साल अक्तूबर में दोबारा चुनाव कराना पड़ा.

फरवरी से अक्तूबर 2005 के बीच नीतीश की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, जबकि रामविलास की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आया. अक्तूबर 2005 में चुनाव के दौरान कराये सर्वे में 42 फीसदी लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश को सबसे पसंदीदा बताया. तब नीतीश की लोकप्रियता राज्य के किसी भी अन्य नेता से अधिक थी. दूसरी ओर, रामविलास की लोकप्रियता में पहले की तुलना में गिरावट आयी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि फरवरी 2005 के चुनाव के बाद सरकार के गठन में रामविलास बाधक बन गये. फरवरी में चुनी गयी त्रिशंकु विधानसभा में सत्ता की चाभी रामविलास के पास ही थी. उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या निर्णायक थी, जिनके समर्थन के बिना किसी सरकार का गठन नहीं हो सकता था. लेकिन पासवान ने किसी दल को समर्थन नहीं देने का फैसला लिया.

सर्वे के दौरान तीनों प्रमुख नेताओं नीतीश, लालू और रामविलास की तुलना करने पर सबसे अधिक 45 फीसदी लोगों ने नीतीश को बिहार का सर्वश्रेष्ठ नेता बताया था. दूसरे स्थान पर लालू प्रसाद रहे थे, जिन्हें 27 फीसदी लोगों ने पसंद किया था. रामविलास को सिर्फ 17 फीसदी लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताया था. छह फीसदी लोगों ने कहा था कि तीनों नेता करीब-करीब एक जैसे ही हैं, जबकि पांच फीसदी ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी.

ऐसा भी नहीं था कि राज्य के अन्य नेताओं पर काफी कम

विश्वास होने के कारण लोगों ने नीतीश को सबसे पसंदीदा नेता बताया. दूसरे राज्यों के नेताओं से तुलना करने पर भी उनकी लोकप्रियता काफी अधिक थी. तब नीतीश से ज्यादा रेटिंग पाने वाले मुख्यमंत्रियों में सिर्फ नवीन पटनायक (ओड़िसा), बुद्धदेव भट्टाचार्य (पश्चिम बंगाल) और नरेंद्र मोदी (गुजरात) शामिल थे.

हालांकि, कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता का ग्राफ नीतीश से थोड़ा ही नीचे था. ये सभी मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता के दम पर पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता दिलाने में सफल रहे.

इस समय बात करें, तो नीतीश अपनी पार्टी से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं. हालांकि, जदयू के बहुत से मतदाता, खासकर मुसलिम, ऐसे भी हैं, जो भाजपा के साथ गंठबंधन को पसंद नहीं करते हैं. बावजूद इसके, नेता के रूप में नीतीश उनकी पहली पसंद बने हुए हैं. संभावना जतायी जा रही है कि नीतीश की यह लोकप्रियता जदयू-भाजपा गंठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में मददगार साबित होगी. हालांकि यह सवाल अब भी बहुतों के मन में है कि क्या मुसलिम भी नीतीश की लोकप्रियता के नाम पर वोट देंगे?

(लेखक सीएसडीएस में फेलो हैं.)

मेरे सपनों का बिहार

विकास के लिए इच्छाशक्ति जरूरी

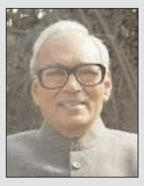

कामता प्रसाद चैयरमेन आइएफआरएमएइडी, दिल्ली

बिहार की वर्तमान स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन जितनी उम्मीद थी. उतना परिणाम नजर नहीं आया है. प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए. सबसे अधिक विकास जहां हुआ है, वह है सड़कें. शानदार लंबी-चौड़ी सड़कें बनवाने में काफी काम किया गया है, लेकिन जनता के जीवनयापन की मूल समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं. क्योंकि गरीब जनता को इसका तब फायदा होगा, जब इन सड़कों का उत्पादन के कार्यों में अधिकाधिक इस्तेमाल होगा. ये तभी हो सकता है, जब कृषि का उत्पादन बढ़े, घरेलू उद्योग बढ़े, लेकिन अब तक की तसवीर को देखते हुए इस तरह की तरक्की के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

दूसरी समस्या बैकों की भी है. बैंकों से ऋण लेने में बिहार

सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है. इसमें भी सुधार के कोई आसार नजर नहीं आते. बिहार के विकास के लिए गांवों का विकास जरूरी है और स्थिति यह है कि ग्रामीण स्तर पर ही बिहार की दशा काफी खराब है. किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, कई लाभकारी योजनाएं प्रशासन की लापरवाही के चलते अधर में ही लटकी रह जाती है. पूरे राज्य की तरक्की के लिए कृषि के विकास के साथ ही सबको रोजगार मिले ये व्यवस्था की जानी चाहिए. बैंकिंग, कॉल सेंटर, एग्रो इंडस्ट्रीज इत्यादि विकसित करने पर ध्यान देना होगा.

बिहार में जागरुकता की बहुत कमी है. इसलिए वहां सामाजिक तबके इतने जागरुक नहीं हैं. लोगों की मानसिकता बहुत संकीर्ण है. इसे दूर करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है. जनसमुदाय की भागीदारी का काम सरकार ही कर सकती है, तब ही सामाजिक तबका तरक्की में कोई भूमिका अदा कर सकेगा. जरूरत है कि जमीनी संस्थाओं को संगठित किया जाये. बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ है कि ये अकेला राज्य कई राज्यों को खाना खिला सकता है. इस परिप्रेक्ष्य में व्यव्स्था की कमी के साथ-साथ इच्छाशक्ति की भी कमी है. अगर आने वाले समय में दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सभी योजनाओं पर काम किया जायेगा तो निश्चित ही बिहार एक सुपर पॉवर बनकर उभर सकता है.

बिहार पोस्ट कार्ड

उन्नत बाजार के रूप में

मैं पिछ्ले पांच वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं. शुरुआती दिनों में मुझे यह कहा जाता था कि तुम्हारे राज्य में जाने पर स्टेशन पर से ही अपहरण कर लिया जाता है. इन सब बातों का श्रेय मीड्यिा को दिया जायेगा, क्योंकि उन दिनों मीड्यिा में कुछ इन्हीं तरीकों की बात कही जाती थी. परंतु आज मीड्यिा ने बिहार की तरक्की की ओर ध्यान दिया है तथा उसे आने वाला एक अच्छा बाजार दिखाया जा रहा है.

इन बातों का खास जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एमबीए का छात्र हूं और बाजार की ओर मेरा ध्यान है. मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बिहार में जाकर काम करूं, लेकिन दलीय राजनीति और कानून व्यवस्था की खस्ता स्थिति बाधा पहुंचा रही रही थी. लेकिन कुछ वर्षों से स्थिति में काफी बदलाव आया है. कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति से राज्य में बाजार भी विकसित हो रहा है. मुझे उम्मीद है कि अब बिहार विकास के रास्ते पर चल चुका है.

सतीश
ग्राम व पोस्ट -सुनौली
जिला: कटिहार, बिहार

(जल्द आने वाली पुस्तक 'सुशासन के आइने में नया बिहार' से)

आंकड़ों का आईना

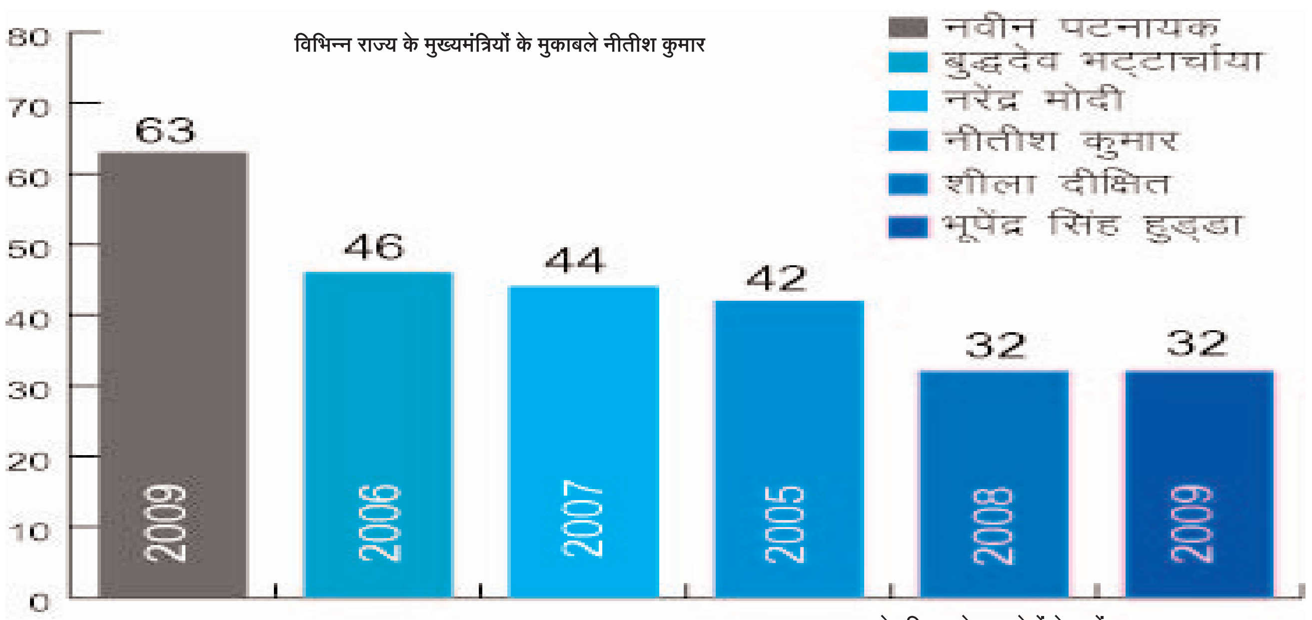

लोकप्रियता के पैमाने पर(फीसदी में)

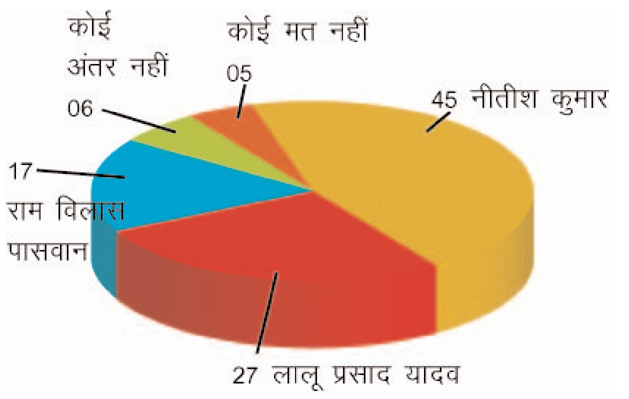

लोकप्रियता के मामले में नेताओं का ग्राफ

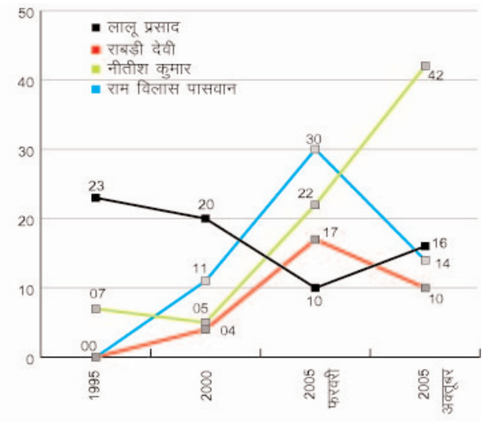

मैं लौटना चाहता हूं

काम का माहौल हो, तो लौटना बेहतर

नाम : देवेंद्र देवेश, उम्र : 35 साल
शहर : कटिहार, जिला : कटिहार
11 साल से दिल्ली में

''अपनी जमीन किसे प्यारी नहीं होती. लेकिन अपने घर पर रहना भी तभी संभव है, जब व्यक्ति को जीवन के लिए जरूरी चीजें मिलती रहें. अगर जीविका के अवसर उपलब्ध न हों, तो घर छोड़ना आदमी की मजबूरी बन जाती है.'' यह कहना है कटिहार जिले के देवेंद्र देवेश का. देवेश साहित्य अकादमी में 'उपसंपादक' के पद पर कार्यरत हैं. वे पिछले ग्यारह सालों से दिल्ली में रह रहे हैं. उन्होंने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्-वविद्यालय, मधेपुरा से हिंदी विषय में पीएचडी की और दिल्ली आ गये. वे कहते हैं कि आदमी दो परिस्थितियों में पलायन को मजबूर होता है. एक तो जहां आप हैं वहां काम ही न मिले. दूसरा काम तो मिले, लेकिन उसका उचित मेहनताना न मिले.

बिहार में समस्या मजदूर वर्ग के साथ खासतौर से है. बिहार में आज भी लोग दबंगई के दम पर लोगों से काम कराते हैं. पैसा देने में मामले में टाल-मटोल कर जाते हैं.

वहां आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक समस्या भी है. वहां कामगारों को प्रतिष्ठा नहीं मिलती. भ्रष्टाचार भी बिहार के पिछड़े रहने का एक कारण है. अन्य राज्यों की तरह वहां गारंटीड भ्रष्टाचार नहीं है. गारंटीड कहने का मतलब है कि दिल्ली या अन्य राज्यों में एक बार घूस दे दिया तो काम हो जाता है, लेकिन बिहार में घूस देने के बाद भी काम नहीं होता. यहां तक कि कई-कई बार घूस देना पड़ता है, तब भी काम नहीं होता.

बिहार में जमींदारी अपने चरम स्वरूप में थी. इसलिए भूदान आंदोलन वहीं से शुरू हुआ. बावजूद इसके, आज भी वहां जमींदारी विद्यमान है. ऐसे लोग हैं जिनके पास कई-कई सौ बीघे खेत हैं. जबकि दूसरी ओर ऐसा तबका है जिसके पास न तो जमीन है और न ही रोजगार. भ्रष्टाचार के कारण बिहार में मूलभूत ढांचा विकसित नहीं हो पाया. काम हुआ, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन सबका सब कागजों में. ऐसे में आने वाली सरकारें वही काम तुरंत नहीं करवा सकती थीं. अंजाम बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है. बिहार में काम का कद्र नहीं है. सरकारों को चाहिए कि वे पहले की सरकारों के कामों को रद्द करने में समय न गंवाकर रचनात्मक काम करें.

रोजगार के अवसर सृजित किये जायें ताकि वहां के लोगों को वहीं काम मिल सके. देवेश कहते हैं कि बिहार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हों कि वहां के लोग वहां रोजगार पा सकें. स्वेच्छा से जाकर कहीं काम करने की बात और है, लेकिन मजबूरन विस्थापन नहीं होना चाहिए. हालांकि, जो लोग बाहर आकर सही स्थिति में हैं उन्हें विस्थापन के दर्द के साथ जीविका का संतोष भी रहता है.

बिहार @ साइबर वर्ल्ड

नेट @ बिहार

पीयूष पांडे

यह बात नयी नहीं है कि बिहार-झारखंड में इंटरनेट की स्थिति देश के कई इलाकों से खराब है. लेकिन, तकनीकी विषयों पर जानकारी देने वाले टेकब्लॉग ने पिछले दिनों लिखी अपनी एक पोस्ट में इन दोनों राज्यों में ब्रॉडबैंड को एक सपना ही करार दे दिया. पोस्ट में लिखा गया-बिहार व झारखंड में इंटरनेट की पहुंच काफी सीमित है. असल समस्या इंटरनेट का शुल्क और बेहद कम विश्वसनीय सेवाएं हैं. जो लोग रुपये खर्च कर इंटरनेट की प्रीमियम सेवाएं लेना भी चाहते हैं, वो भी अविश्वसनीय सेवाओं से बच नहीं पाते. बीएसएनल के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में कहा गया है कि जब यह चलता है तो ठीक है, लेकिन पटना जैसे शहर में भी कनेक्शन खराब हुआ तो तीन-चार दिन ठीक होने में लग जाते हैं. इस कनेक्शन के आधार पर ब्लॉगिंग और वेबसाइट्स जैसे जुड़े कारोबार करना संभव नहीं है. इस पोस्ट में सिफी के वर्ल्डफोन की ब्रॉडबैंड सेवाएं भयानक बतायी गयी हैं.

एमटीएस की सीडीएमए तकनीक पर आधारित ब्रॉडबैंड की हालत भी काफी खराब है. टाटा की ब्रॉडबैंड सेवा कुछ महंगी है, लेकिन इसकी हालत कुछ ठीक है. गौरतलब है कि अंजन नाम के जिस शख्स ने यह पोस्ट लिखी है, उन्होंने संभवत: अपने चंद दिनों के बिहार प्रवास के दौरान अपने इंटरनेट अनुभव लिखे हैं. लेकिन, हालात बहुत बेहतर हैं-ऐसा तो नहीं है. पटना-रांची जैसे कुछ शहरों को छोड़ दें, तो अभी कई दूसरे शहरों में इंटरनेट की स्थिति खासी खराब है. ग्रामीण इलाकों की बात करना तो बेकार है. वैसे, अकामाई टेक्नोलॉजी के सर्वे में देश में इंटरनेट स्पीड के मामले में भी बिहार कहीं नहीं था. केरल, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शुरुआती दस राज्यों में थे. दिलचस्प है कि बिहार से बाहर बैठकर साइबर दुनिया को खंगाल रहे लोग एक ओर बाबू लाल मरांडी के फेसबुक पर आने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ब्लॉगिंग में छाने की ख़बरों से रुबरु होते हैं, तो दूसरी तरफ टेकब्लॉग की पोस्ट और अकामाई की रिपोर्ट से भी टकराते हैं. जाहिर है, ब्रांड बिहार बनाने के लिए इंटरनेट की मौजूदगी, बेहतर सेवा और स्पीड भी अहम मुद्दा है?

राष्ट्रीय फलक

अयोध्या और अल्पसंख्यक मुद्दे पर गरमाती राजनीति

कमलेश कुमार सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दे सियासी गलियारे में गर्माहट पैदा कर रहे हैं. इन्हीं मसलों में अयोध्या पर अदालती फैसले का भाजपा-जदयू गंठबंधन पर संभावित प्रभाव भी एक है. ***टाइम्स ऑफ इंडिया*** की एक खबर के मुताबिक,भाजपा ने फिलहाल सीटों के बंटवारे के मसले पर चुप्पी साध रखी है. 24 तारीख को अयोध्या मसले पर अदालत का फैसला आना है. फैसला अगर भाजपा की राजनीतिक कसौटी पर खरा उतरता है, तो वह जदयू से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है. यही कारण है कि पार्टी के राज्य नेता अभी भी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे के सवाल पर चुप्पी साध रखी है. भाजपा नवंबर 2005 में हुए चुनाव में 103 सीटों पर चुनाव लड़ी थी.

दूसरी ओर ***द हिंदू*** ने अल्पसंख्यकों के मसले पर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर आधारित एक खबर छापी है. इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान को माध्यम बनाया गया है. खबर के मुताबिक, सलमान खुर्शीद अपने मंत्रालय का अर्द्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि बिहार सरकार केंद्रीय मद के पैसा का उपयोग नहीं कर रही है. नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुसलिम बहुल इलाकों के विकास के लिए केंद्र सरकार उचित फंड मुहैया नहीं करायी है. इस आरोप का जवाब देते हुए खुर्शीद ने कहा कि राज्य सरकार एमएसडीपी प्रोजेक्ट फंड का केवल 19.20 प्रतिशत ही खर्च पायी है, जबकि इस मद में 122 करोड़ रुपये आवंटित की गयी है. पहले सरकार को इस फंड की राशि को खर्च करना चाहिए. जबकि इसी फंड का मणिपुर द्वारा 42, झारखंड द्वारा 40 और जम्मू-कश्मीर द्वारा 36 प्रतिशत खर्च किया गया है. इसी वर्ष जुलाई में मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में खुर्शीद ने तमाम आरापों को खारिज किया था.